

मरिजापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में बनेगा जनजातीय संग्रहालय

चर्चा में क्यों?

31 अक्टूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने मरिजापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में बनने वाले जनजातीय संग्रहालय के लिये प्रस्तावित ज़मीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने के केंद्र सरकार के फैसले को अनापत्ति दी है।

प्रमुख बिंदु

- वदिति हो कि उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियों सूचीबद्ध हैं। उनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिये मरिजापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा।
- जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये संबंधित ज़िलाधिकारियों द्वारा ज़मीन संस्कृति विभाग लखनऊ को आवंटित की गई है।
- प्रत्येक संग्रहालय के लिये केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपए देगी। इसमें राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा।
- संग्रहालय के लिये मरिजापुर में अतरैला पांडेय गाँव में 4.046 हेक्टेयर ज़मीन, सोनभद्र में राबर्टसगंज में 2.82 हेक्टेयर ज़मीन और महाराजगंज की नौतनवा तहसील में 0.506 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित की जाएगी।
- संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी जानकारियों, सूचनाओं, फ़िल्मों, चित्रों आदि का प्रदर्शन डिजिटल थियेटर में किया जाएगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय किया जाएगा।